



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937

No. 694]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015/CHAITRA 11, 1937

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय****आदेश**

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2015

**का.आ. 924(अ).**—संयुक्त निदेशक (लेखा), अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ उक्त धारा के अधीन समामेलनकारी कंपनी के किसी सदस्य या लेनदार डिबेंचरधारक सहित को संदेय क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के लिए “सक्षम प्राधिकारी”, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के नियम 12-क के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित के संबंध में, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 के अधीन नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (विघटित कंपनी) का उसकी नियंत्री कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिज (इंडिया) लिमिटेड (अंतरीति कंपनी) के साथ प्रस्तावित समामेलन के मामले में

और

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (3) के निबंधनानुसार नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (विघटित कंपनी) के सदस्यों और लेनदारों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण के मामले में

1. केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 21 अक्तूबर, 2014 के अपने प्रारूप आदेश द्वारा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनएसईएल कहा गया है) का उसकी नियंत्री कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिज (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् एफटीआईएल कहा गया है) के साथ समामेलन किया था।

2. और, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी उक्त प्रारूप आदेश के अनुसरण में एफटीआईएल ने माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 2743/2014 फाइल की है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी उक्त प्रारूप आदेश को चुनौती दी गई है। माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर, 2014 को हुई उसकी सुनवाई में, अन्य बातों के साथ-साथ, पक्षकारों को यह निदेश दिया है कि वे ‘यथास्थिति’ बनाए रखें और केन्द्रीय सरकार सुनवाई की अगली तारीख तक आगे कोई

कदम नहीं उठाएगी तथा 22 दिसंबर, 2014 को आदेश दिया कि 27 नवंबर को पारित, यथास्थिति, आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा जिसे 4 फरवरी, 2015 नियत किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी, 2015 को हुई उसकी सुनवाई में समामेलन के प्रारूप आदेश पर यथास्थिति आदेश निष्प्रभावी कर दिया और, अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट किया कि केन्द्रीय सरकार ऐसे अन्य आदेश जारी कर सकती है जो वह विधि के अनुसार उचित और उपयुक्त समझे।

3. और, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुरूप, समामेलन से पूर्व प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक सदस्य या लेनदार (डिबेंचरधारक सहित) की, यथा शक्य, समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कंपनी में समान हित या अधिकार होंगे जो उस कंपनी में प्राप्त थे जिसका वह मूल रूप में सदस्य या लेनदार था; और ऐसे सदस्य या लेनदार के हित या अधिकार उस सीमा तक प्रतिपूर्ति का हकदार होगा जो नियमों द्वारा यथाउपबंधित ऐसे प्राधिकारी समामेलन के परिणामस्वरूप बने कंपनी में मूल कंपनी के उसके हितों या अधिकार से कम निर्धारण किया जाए।

4. और, कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के नियम 12क के अनुरूप, कंपनी कार्य विभाग में संयुक्त निदेशक (लेखा) {"सक्षम प्राधिकारी"} धारा 396 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ उक्त धारा के अधीन समामेलित हो रही कंपनी के किसी सदस्य या लेनदार (डिबेंचरधारक सहित) को संदेय निर्धारण हेतु प्राधिकारी होंगे।

5. और, अधोहस्ताक्षरी को आदेश संख्या ए-22011/1/2014-प्रशा.॥ तारीख 27 अक्तूबर, 2014 द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (3) के साथ पठित कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 (1956 का 1) के नियम 12-क के अधीन संयुक्त निदेशक (लेखा) के रूप में पदाभिहित किया गया था और इसलिए अधोहस्ताक्षरी निर्धारण हेतु यह आदेश पारित करने के लिए सक्षम हैं।

6. और, केन्द्रीय सरकार ने अपने पत्र संख्या 3/170/2014-सीएल-॥ तारीख 20 नवंबर, 2014 द्वारा मैसर्स लोढा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दोनों कंपनियों का मूल्य अवधारण करने के लिए और शेयर विनिमय अनुपात प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। केन्द्रीय सरकार ने रिसर्जेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेबी से मान्यता प्राप्त मर्चेन्ट बैंकर को भी मैसर्स लोढा एंड कंपनी द्वारा अवधारित मूल्य पर निष्पक्ष मत जारी करने के लिए नियुक्त किया था।

7. और, मैसर्स लोढा एंड कंपनी ने दिनांक 06 मार्च, 2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और तदनुसार, मर्चेन्ट बैंकर ने मैसर्स लोढा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संचालित मूल्यांकन की निष्पक्षता की पुष्टि करते हुए 13 मार्च, 2015 को मूल्यांकन और विनिमय अनुपात पर अपना निष्पक्ष राय दी है।

8. और, एफटीआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी है और इसकी प्रदत्त पूंजी 9,21,57,074 रुपए हैं जो 30 सितंबर, 2014 को दो रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ 46078537 इक्विटी शेयरों में है।

9. और, एनएसईएल एक असूचीबद्ध कंपनी है और इसने 31 मार्च, 2013 तक ही अपना वार्षिक लेखा फाइल किया है और इसके वित्तीय आंकड़े उसी तारीख तक उपलब्ध हैं। तथापि, प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए इसके वित्तीय लेखों से भरोसा हटा लिया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि पूंजी के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए फाइलिंग के अनुसार 31 मार्च, 2014 को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एफटीआईएल की एक अनुषंगी कंपनी) की समादत्त शेयरपूंजी 45,00,00,000 रुपए है जिसमें 10 रुपए प्रत्येक के 4,50,00,000 इक्विटी शेयर हैं। शेयरहोल्डिंग के ब्यौरे निम्नलिखित हैं -

शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या (10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर)	राशि (रुपए में)
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिज (इंडिया) लिमिटेड	4,49,99,895	44,99,98,950
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)	100	1000
जिग्नेश प्रकाश शाह (एफटीआईएल के नामनिर्देशिती)	1	10
अरशद मोहम्मद खान (एफटीआईएल के नामनिर्देशिती)	1	10
मंजय प्रकाश शाह (एफटीआईएल के नामनिर्देशिती)	1	10
वी. हरिहरन (एफटीआईएल के नामनिर्देशिती)	1	10
जोसेफ डेनियल मेस्सी (एफटीआईएल के नामनिर्देशिती)	1	10
<b>योग</b>	<b>4,50,00,000</b>	<b>45,00,00,000</b>

10. और, तारीख 21 अक्तूबर, 2014 के समामेलन के प्रारूप आदेश के पैरा 3 के खंड (ख) में यह उल्लेख किया गया है कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, जो अब अपने नामनिर्देशितियों सहित फाइनेंसियल टेक्नोलॉजिज (इंडिया) लिमिटेड के पास है, में पूर्णतया संदाय किए गए 10 रुपए के सभी 44999895 इक्विटी शेयर रद्द कर दिए जाएंगे।

11. और, मैसर्स लोघा एंड कंपनी में स्वतंत्र मूल्यांकक के रूप में नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंटों में एफटीआईएल के प्रति शेयर का उचित मूल्य 208/- रुपए (दो सौ आठ रुपए मात्र) करने की सिफारिश की है। एनएसईएल एक असूचीबद्ध कंपनी है और चार विभिन्न स्थितियों, जिनमें से दो मूल्यांककों द्वारा सिफारिश की गई, पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि एनएसईएल के प्रबंधन और लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए इसके वित्तीय लेखों से भरोसा हटा लिया है, इसका उचित मूल्य 0 (शून्य) रुपए से 77/- रुपए की सीमा में शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पद्धति पर की सिफारिश की गई है।

12. और, निम्नलिखित दो परिदृश्यों में स्वतंत्र मूल्यांकक 0 रुपए (शून्य) से 77.40 रुपए प्रतिशेयर की श्रेणी में एनएसईएल के उचित मूल्य पर पहुंचे, अर्थात् :-

(क) वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए उचित मूल्य 77.40 रुपए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य प्रणाली पर यह मानते हुए किया गया कि क्रेताओं (उधारकर्ताओं) से प्राप्त पूरी वसूली से विक्रेताओं (निवेशकों) को मुआवजा दिया जाएगा;

(ख) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए उचित मूल्य 0 (शून्य) रुपए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य प्रणाली पर यह मानते हुए किया गया कि विक्रेताओं (निवेशकों) के मुआवजा का निपटान नहीं किया जाएगा और 371.64 करोड़ रुपए की सीमा, जो मूल्यांकन तारीख तक वसूली की गई, के अतिरिक्त वसूली मानते हुए क्रेताओं (उधारकर्ताओं) से और वसूली नहीं हो सकती है।

13. और, किए गए मूल्यांकन के आधार पर स्वतंत्र मूल्यांककों ने एफटीआईएल के 2 रुपए प्रति पूर्णतया समादत्त इक्विटी शेयरों के 0 (शून्य) से 3 (तीन) के स्वैप अनुपात को एनएसईएल के 10 रुपए प्रति पूर्णतया समादत्त इक्विटी शेयरों वाले 8 (आठ) शेयरों के बदले जारी करने की सिफारिश की है।

14. अतः, अब कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के नियम 12-क के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 396 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी एफटीआईएल (परिणामी कंपनी) के विरुद्ध एनएसईएल (विघटित कंपनी) के सदस्यों और लेनदारों के मुआवजे के निर्धारण के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करता है, अर्थात् -

(1) **एनएसईएल के सदस्यों के मुआवजे का निर्धारण-** मूल्यांकन और केन्द्रीय सरकार द्वारा पास किए जाने वाले अंतिम आदेश, यदि कोई है, के अधीन और अंतिम आदेश के अनुसार एनएसईएल (विघटित कंपनी) की संपत्तियों, परिसंपत्तियों, देनदारियों और दायित्व के हस्तांतरण और अधिकार एफटीआईएल (परिणामी कंपनी) को प्रदान करने के संबंध में परिणामी कंपनी किसी अतिरिक्त कार्यवाही या कार्य के बिना पूर्णतया समादत्त इक्विटी शेयर की स्वामित्व वाली विघटित कंपनी जिसका नाम रिकार्ड तारीख में विघटित कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा है या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऐसे संबंधित वारिस, निष्पादक, प्रशासक, समनुदेशिनी या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों या अन्य हक उत्तराधिकारी हैं, के दस रुपए वाले प्रत्येक आठ इक्विटी शेयरों के लिए दो रुपए प्रति पूर्णतया सद्त्त इक्विटी शेयर वाले तीन शेयर जारी और आबंटित करेगी।

(क) ऊपर्युक्त पैरा (i) में उल्लिखित ऊपर्युक्त परस्पर विनिमय का आकलन तारीख 31 मार्च, 2012 को उपलब्ध एनएसईएल के अद्यतन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के मद्देनजर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित और ऊपर्युक्त पैरा 12 खंड (क) में विक्षेपित परिदृश्य 1 के अनुसार 77 रुपए प्रति शेयर के रूप में एनएसईएल को उचित मूल्य पर विचार करते हुए किया जाता है। लेखापरीक्षकों और एनएसईएल के प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 का वित्तीय विवरण वापस लौटा दिया गया। ऊपर पैरा 12 खंड (ख) में प्रगणित किए गए अनुसार मूल्यांककों द्वारा निर्धारित अन्य स्थिति में एनएसईएल के वैकल्पिक उचित मूल्य नहीं माना गया, क्योंकि निवेशकों से संबंधित देनदारियों का मामला वर्तमान में विवाद का विषय है। दोनों विकल्पों में से बेहतर विकल्प के लिए अल्प संख्या शेयर धारकों के हित पर विचार किया गया है।

(ख) ऊपर दिए गए पैरा (i) के अनुसार इक्विटी शेयर के आबंटन से उद्भूत भिन्न को निकटतम पूर्णांक में पूर्ण कर दिया जाएगा।

- (ग) विघटित कंपनी के शेयरधारक जिसे पैरा (i) के अनुसरण में हस्तांतरिती कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर जारी किए जाने हैं, को यथास्थिति अभौतिक रूप या भौतिक रूप में शेयर जारी किए जाएंगे।
- (घ) विघटित कंपनी में 10 रूपए प्रति शेयर वाले पूर्णतया: सदंत सभी 4,49,99,895 इक्विटी शेयर, जो एफटीआईएल (हस्तांतरिती कंपनी) के नाम पर होंगे, तथा एक एक शेयर नामनिर्देशितियों में से हरेक द्वारा धारित है, पांच शेयरों को रद्द किया जाएगा।
- (ङ) अंतरिती कंपनी द्वारा दिए जाने वाली प्रतिपूर्ति—

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (10/- रूपए प्रत्येक का इक्विटी शेयर)	राशि	क्षतिपूर्ति (अंतरिती कंपनी के शेयरों की संख्या)
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)	100	1,000	37.5
एफटीआईएल द्वारा जारी किए जाने वाले कुल शेयर (लगभग)			38

(2) एनएसईएल के लेनदारों की क्षतिपूर्ति का निर्धारण : जहां तक लेनदारों की प्रतिपूर्ति का संबंध है तारीख 21 अक्तूबर, 2014 के प्रारूप आदेश के खंड 4 के उपखंड (1) में, अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध है कि, “ऐसा अंतरण और विहित करना नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड की उक्त संपत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी बंधकों और प्रभारों तथा आडमानों, गारंटी और सभी अधिकारों, जो भी हो के अधीन होगा”। प्रारूप आदेश के खंड 6 में कानूनी कार्यवाही को सुरक्षित रखने का भी उपबंध है। उक्त प्रारूप आदेश के खंड 8 में कराधान से सुरक्षा का भी उपबंध है जबकि उक्त प्रारूप आदेश का खंड 9 विघटित कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का संरक्षण करता है तथा उक्त प्रारूप का आदेश खंड 11 भविष्यनिधि और अन्य कर्मचारी कल्याण योजनाओं की सदस्यता का उपबंध करता है। इस प्रकार ये खंड उक्त अधिनियम की धारा 396 की उपधारा (3) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ उपबंध है कि प्रत्येक कंपनी के समामेलन से पहले प्रत्येक लेनदारों का वही हित या अधिकार होगा जो उसे मूलतः एक लेनदारों के रूप में कंपनी में मिलता। अतः विघटित कंपनी के ऋणदाताओं के हित या अधिकार विघटित कंपनी के विरुद्ध उनके हितों या अधिकार कम करने का प्रस्ताव नहीं है और मेरे विचार में लेनदारों की प्रतिपूर्ति के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु इस आदेश का माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों के साथ पठित समामेलन के तारीख 21 अक्तूबर, 2014 के प्रारूप आदेश पर केंद्रीय सरकार के अंतिम निर्णय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। यह आदेश तभी और केवल तभी प्रभावी होगा जबकि केंद्रीय सरकार नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का उसकी नियंत्रिती कंपनी फाइनेंशियल टेक्नॉलाजिस (इंडिया) लिमिटेड के साथ समामेलन करने का निर्णय लेती है।

(4) क्षतिपूर्ति के इस निर्धारण से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 396 की उपधारा 3 के खंड (क) के अधीन यथा उपबंधित इस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर कंपनी विधि बोर्ड में अपील कर सकेगा।

[फा. सं.3/170/2014-सीएल-II]

मनमोहन जुनेजा, संयुक्त निदेशक (लेखा)

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### ORDER

New Delhi, the 1st April, 2015

**S.O. 924(E).**—In exercise of powers conferred by section sub section (3) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and read with rule 12-A of The Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, the Joint Director (Accounts), that is, the competent authority to assess the compensation for the purpose of sub-section (3) of section 396 of the said Act, payable to a member or creditor, including debenture holder, of the company amalgamating under that section, hereby makes the following order, in respect of the following, namely:—

In the matter of: Proposed Amalgamation of National Spot Exchange Limited (dissolved company) with its holding company, Financial Technologies (India) Limited (transferee company), under section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)

And

In the matter of: Assessment of compensation to members and creditors of National Spot Exchange Limited (dissolved company) in terms of sub-section (3) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)

1. Whereas the Central Government had issued a draft order causing amalgamation of National Spot Exchange Limited (hereinafter NSEL) with its holding company Financial Technologies (India) Limited (hereinafter FTIL) in exercise of the powers conferred by section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) vide its draft order dated the 21st October, 2014.

2. And whereas pursuant to the said draft order issued by the Central Government, FTIL has filed a Writ Petition No. 2743 of 2014 before Hon'ble Bombay High Court, challenging the said draft order issued by the Central Government. The Hon'ble Bombay High Court in its hearing held on 27<sup>th</sup> November, 2014, inter-alia, directed the parties to maintain 'status quo' and no further steps shall be taken by the Central Government till next date of hearing and on 22<sup>nd</sup> December, 2014, ordered for the continuation of status quo order passed on 27<sup>th</sup> November, 2014 till next date which was fixed for 4<sup>th</sup> February, 2015. The Hon'ble High Court in its hearing held on 4<sup>th</sup> February, 2015, vacated the status quo on draft order of amalgamation and clarified, inter-alia, that the Central Government may pass such other orders which it deems fit and proper in accordance with law.

3. And whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), every member or creditor (including a debenture holder) of each of the companies before the amalgamation shall have, as nearly as may be, the same interest in or rights against the company resulting from the amalgamation as he had in the company of which he was originally a member or creditor; and to the extent to which the interest or rights of such member or creditor in or against the company resulting from the amalgamation are less than his interest in or rights against the original company, he shall be entitled to compensation which shall be assessed by such authority as may be provided by rules.

4. And whereas, in accordance with the rule 12-A of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, the Joint Director (Accounts) {"Competent authority"} in the Department of Company Affairs shall be the authority to assess the compensation for the purpose of sub-section (3) of section 396 of the said Act, payable to a member or creditor (including debenture holder) of the company amalgamating under that section.

5. And whereas the undersigned was designated as Joint Director (Accounts) under rule 12-A of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 read with the provisions of sub-section (3) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) vide order No. A-22011/1/2014-Ad-II dated the 27<sup>th</sup> October, 2014 and hence the undersigned is competent to pass this for Assessment.

6. And whereas the Central Government, vide its letter No. 3/170/2014-CL.II dated the 20<sup>th</sup> November, 2014, appointed M/s Lodha & Co., Chartered Accountants as an Independent Valuer to determine the valuation of both the companies and to arrive the share exchange ratio. The Central Government also appointed Resurgent India Private Limited, a SEBI recognised Merchant Banker to issue fairness opinion on the valuation determined by M/s. Lodha & Co.

7. And whereas, M/s. Lodha & Co. had submitted its Report dated the 6<sup>th</sup> March, 2015 and accordingly, the Merchant Banker has given fairness opinion on the Valuation and Exchange Ratio on the 13<sup>th</sup> March, 2015 confirming the fairness of the valuation conducted by M/s Lodha & Co, Chartered Accountants.

8. And whereas, FTIL is a listed company and is having paid-up capital of Rs. 9,21,57,074 divided into 4,60,78,537 equity shares with a face value of Rs. 2 each as on 30<sup>th</sup> September, 2014 .

9. And whereas NSEL is an unlisted company and has filed its Annual Accounts as at 31<sup>st</sup> March, 2013 only and the financial data is available only up to this date. However, the management and the auditors have withdrawn reliance on the financials for financial year 2012-13. However, it is noted that as per the filings made by the company with regard to the capital that as on 31<sup>st</sup> March, 2014 the National Spot Exchange Limited (a subsidiary company of FTIL) is having a paid up share capital of Rs. 45,00,00,000 consisting of 4,50,00,000 equity shares of Rs. 10 each. The details of shareholding is as under:

Name of Shareholders	No. of shares held (equity shares of Rs. 10 each)	Amount (Rs.)
Financial Technologies (India) Limited	4,49,99,895	44,99,98,950
National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED)	100	1,000
Jignesh Prakash Shah (nominee of FTIL)	1	10
Arshad Mohamed Khan (nominee of FTIL)	1	10
Manjay Prakash Shah (nominee of FTIL)	1	10
V. Hariharan (nominee of FTIL)	1	10
Joseph Daniel Massey (nominee of FTIL)	1	10
<b>Total</b>	<b>4,50,00,000</b>	<b>45,00,00,000</b>

10. And whereas it is provided in clause (b) of Para 3 of the draft order of amalgamation dated the 21<sup>st</sup> October, 2014 that all the 4,49,99,895 equity shares of Rs.10 each fully paid up in National Spot Exchange Limited, which are now held in the name of Financial Technologies (India) Limited including its nominees, shall be cancelled.

11. And whereas M/s. Lodha & Co, Chartered Accountants appointed as independent valuers have recommended fair value per share of FTIL at Rs. 208 (Rupees two hundred eight only). NSEL is an unlisted company and its fair value has been recommended on Net Asset Value Method in the range of Rs. 0 (Zero) to 77 (Rupees seventy seven only) considering four various scenarios of which only two have been recommended by the valuers and also considering the fact that the management of NSEL and auditors have withdrawn reliance on the financials for Financial Year 2012-13.

12. And whereas the independent valuers have arrived at the fair value of NSEL in the range of Rs. 0 (zero) to Rs. 77.40 per share in the following two scenarios, namely:-

- (a) fair value has been arrived at Rs. 77.40 per share on net asset value method on the basis of audited financial statement for the financial year 2011-2012 assuming sellers' (investors) claims would be settled with full recovery from buyers (borrowers);
- (b) fair value has been arrived at Rs.0 (zero) on net asset value method on the basis of the audited financial statement for the financial year 2011-2012 assuming sellers (investor) claim would not be settled and no further recovery can be made from the buyers (borrowers) considering the recovery trend except to the extent of Rs. 371.64 crore which has been recovered till valuation date.

13. And whereas on the basis of the valuation conducted, the independent valuers have recommended swap ratio of 0 (Zero) to 3 (Three) fully paid up equity shares of Rs. 2 each of FTIL to be issued in exchange of Eight fully paid up equity shares of Rs. 10 each of NSEL.

14. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 396 of the said Act read with rule 12-A of Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, the undersigned passes the following order for assessment of compensation to the members and creditors of NSEL (dissolved company) against FTIL (resulting company), namely:-

(1) **Assessment of Compensation to members of NSEL:**—Subject to the valuation and upon coming into the effect of the final order to be passed by the Central Government, if any, and in consideration for the transfer of and vesting of the properties, assets, liabilities and undertaking of the NSEL (dissolved company) in the FTIL (resulting company) in terms of the final order, the resulting company shall without any further act or deed, issue and allot three fully paid-up equity shares of rupees two each for every eight equity shares of Rs. 10 each held in the dissolved company, holding fully paid up equity shares and whose names appear in the Register of Members of the dissolved company on the record date or to such of their respective heirs, executors, administrator, assignee, or other legal representatives or other successors in title as may be recognised by the Central Government.

- (a) the above swap exchange ratio at para (i) above is arrived at considering the fair value of NSEL as Rs. 77 per share as per scenario 1 arrived at by the independent valuers and enumerated at clause (a) para 12 above keeping in view that the latest audited financial statements of NSEL available are as on 31<sup>st</sup> March, 2012. The Financial Statements for the financial year 2012-13

have since been withdrawn by the auditors and the management of NSEL. The alternative fair value of NSEL at Rs. 0 (zero) arrived at by the valuers in the other scenario as enumerated at clause (b) of para 12 above has not been considered because of the fact that the issue of liabilities pertaining to investors is presently subject matter of dispute. A better of the two alternatives is considered in the interest of the minority shareholders.

- (b) Any fraction arising out of allotment of equity shares as per para (i) above shall be rounded off to the nearest integer.
- (c) The shareholder of the dissolved company, to whom the equity shares are to be issued by the transferee company pursuant to para (i), shall be issued these shares in dematerialized form or physical form as the case may be.
- (d) All the 4,49,99,895 equity shares of Rs. 10 each fully paid up in dissolved company, which would be in the name of FTIL (transferee company) and five shares, one each held by each of its nominees, shall be cancelled.
- (e) Compensation to be discharged by transferee company –

Name of Shareholders	No. of shares held (Equity shares of Rs. 10 each)	Amount	Compensation (No. of shares of Transferee Company)
National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED)	100	1,000	37.5
<b>Total Share to be issued by FTIL (rounded off)</b>			<b>38</b>

(2) **Assessment of compensation to Creditors of NSEL:**—As far as the compensation to creditors is concerned, it is provided in sub-clause (1) of Clause 4 of the draft order dated the 21<sup>st</sup> October, 2014 that, inter-alia, “*Such transfer and vesting shall subject to all mortgages and charges and hypothecation, guarantees and all rights whatsoever affecting the said properties of National Spot Exchange Limited*”. Clause 6 of the draft order further provides for saving of legal proceedings. Clause 8 of the said draft order also provides for protection of Taxation, while Clause 9 of the said draft order protects the officers and employees of dissolved company and Clause 11 of the said draft order provides for membership of provident fund and other employee benefit schemes. Thus, these clauses are meeting the requirements of sub-section (3) of section 396 of the said Act which inter-alia, provides that every creditor of each of the companies before amalgamation shall have, as nearly as may be, the same interest in or rights against the company resulting from amalgamation as he had in the company of which he was originally a creditor. Therefore, the interest in or rights of the creditors of dissolved company as against the resulting company are not proposed to be less than their interest in or rights as they had against the dissolved company and thus I feel no need for assessment of compensation to the creditors.

(3) This order for assessment of compensation is without prejudice to the final decision of the Central Government on the draft order dated the 21<sup>st</sup> October, 2014 of amalgamation read with directions of the Hon’ble Bombay High Court. This order shall be effective, if and only if, the Central Government finally decides to amalgamate National Spot Exchange Limited with its holding company Financial Technologies (India) Limited.

(4) Any person aggrieved by this assessment of compensation may prefer an appeal to the Company Law Board within thirty days from the publication of this order in the Official Gazette as provided under sub-section (3A) of section 396 of the said Act.

[F. No. 3/170/2014- CL-II]

MANMOHAN JUNEJA, Jt. Director (Accounts)